Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 27-06-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 27 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus :** GS 2 : International Relations	भारत ने पहलगाम को बाहर रखने पर एससीओ में संयुक्त बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया
Page 01 **Syllabus :** GS 3 : Science & Technology	शुक्ला आईएसएस में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने
Page 05 **Syllabus :** GS 2 : Indian Polity	पूर्व सीजेआई: क्रमिक चुनावों को संविधान की अपरिवर्तनीय विशेषता नहीं माना जा सकता
Page 07 **Syllabus :** GS 2 : International Relations	बैंकॉक कार्यक्रम में, हर जन्म और मृत्यु की गिनती करने की प्रतिबद्धता
Page 10 **Syllabus :** GS 1 : Art & Culture	कीलाडी विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus :** GS 3 : Science & Technology	एआई प्रसार को प्रबंधित करने की अमेरिका की योजना की समझ

Page 01 : GS 2 : International Relations

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की क़िंगदाओ, चीन में आयोजित बैठक में संयुक्त बयान को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि इस दस्तावेज़ में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों का ज़िक्र था।

India declines to endorse joint statement at the SCO over exclusion of Pahalgam

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

India declined to endorse the joint statement at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers' meeting in China, and pushed for including tougher language on terrorism that would reflect the Indian position, particularly in the wake of the Pahalgam terror attack on April 22.

Sources said Defence Minister Rajnath Singh refused to sign the document on Thursday as it did not mention the Pahalgam attack but included militant activities in Balochistan. Pakistan and China were trying to divert attention from terrorism, and the document would have diluted India's position on critical issues, particularly terrorism and regional security, sources added.

In his address at the SCO meet in Qingdao, Mr. Singh said a terror group, The Resistance Front, had carried out a "dastardly and heinous attack" on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir, killing 26 innocent civilians, including a Nepali national. The TRF, a proxy of the UN-designated Lashkar-e-Taiba, had claimed responsibility for the attack, he said.

"Peace and prosperity cannot co-exist with terrorism and proliferation of Weapons of Mass Destruction in the hands of non-state actors and terror groups. Dealing with these challenges requires decisive action. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilise terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticise such nations," Mr. Singh said.

Defence Minister Rajnath Singh with his Chinese counterpart Dong Jun in Qingdao. ANI VIDEO GRAB

मुख्य बिंदु:

1. **भारत की आपत्ति:**
   - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

- भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अधिक कठोर भाषा की मांग की, जिससे उसका पक्ष स्पष्ट रूप से सामने आ सके, विशेषकर पहलगाम हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था।
- भारत को चिंता थी कि यदि संयुक्त बयान में कुछ क्षेत्रों में आतंकवाद की निंदा की जाए और अन्य को अनदेखा किया जाए, तो इससे सीमा-पार आतंकवाद की गंभीरता कम आँकी जाएगी।

2. **पहलगाम आतंकी हमला:**
   - इस हमले को द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने अंजाम दिया, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है।
   - TRF एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठन है।
   - यह हमला निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया था, जो यह दर्शाता है कि सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क अभी भी एक गंभीर खतरा बने हुए हैं।
3. **SCO में भारत की स्थिति:**
   - राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद और गैर-राज्य अभिनेताओं के हाथों में जनसंहारक हथियारों का प्रसार वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
   - उन्होंने उन देशों की आलोचना की जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं — यह संकेत पाकिस्तान की ओर था।
   - भारत ने SCO में आतंकवाद के खिलाफ एक समान और सशक्त रुख अपनाने की मांग की, जिसमें कोई राजनीतिक समझौता या दोहरा मापदंड न हो।
4. **भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य:**
   - संयुक्त बयान में बलूचिस्तान का उल्लेख और पहलगाम का बहिष्कार यह दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान इस विमर्श को मोड़ने का प्रयास कर रहे थे।
   - भारत का बयान को समर्थन न देना इस बात का संकेत है कि वह आतंकवाद की आंशिक निंदा को स्वीकार नहीं करेगा।

भारत की विदेश नीति पर प्रभाव:

- **आक्रामक कूटनीति:** यह भारत की बहुपक्षीय मंचों पर अपने मुख्य राष्ट्रीय हितों, विशेषकर आतंकवाद के मुद्दे पर, सख्त और स्पष्ट नीति को दर्शाता है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** यह क्षेत्रीय सुरक्षा विमर्श में चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक एकजुटता को लेकर भारत की चिंताओं को पुष्ट करता है।
- **वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता:** भारत की यह कार्रवाई उसकी आतंकवाद के विरुद्ध स्थायी और सख्त नीति को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करती है।
- **बहुपक्षीय मंचों की सीमाएँ:** यह SCO जैसे संगठनों की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जहाँ भू-राजनीतिक हित सामूहिक सुरक्षा उद्देश्यों पर हावी हो जाते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का SCO के संयुक्त बयान का समर्थन न करना उसकी आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति और निष्पक्ष वैश्विक आतंकवाद-रोधी ढाँचे की माँग का स्पष्ट संकेत है। यह कदम बहुपक्षीय सहयोग की उन व्यापक चुनौतियों को भी दर्शाता है, जहाँ अक्सर सामूहिक सुरक्षा की भावना को भू-राजनीतिक स्वार्थों के अधीन कर दिया जाता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques : "एससीओ संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करने से भारत का इनकार आतंकवाद के सामने बहुपक्षीय कूटनीति की जटिलताओं को उजागर करता है।" भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 Words)**

Page 01: GS 3 : Science & Technology

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। वह Axiom Mission 4 (Ax-4) का हिस्सा बनकर ISS में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर गगनयान मिशन, के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Shukla becomes first Indian to enter the ISS

IAF Group Captain is the pilot of the much-delayed mission and will spend two weeks on the space station; he is one of the four astronauts designated to take part in Gaganyaan mission

The Hindu Bureau
CHENNAI

Group Captain Shubhanshu Shukla of the Indian Air Force created history on Thursday afternoon by becoming the first Indian to enter the International Space Station.

As the Dragon crew capsule carrying Mr. Shukla and three other astronauts as part of Axiom Mission 4 (Ax-4) circled earth, he greeted people back home with a "*Namaskar* from space". The spacecraft then docked with the ISS at 4.01 p.m. IST as it passed over the north Atlantic Ocean.

For Mr. Shukla, this is the first step to a more ambitious mission as he is one of the four astronauts designated to take part in Gaganyaan, India's first human spaceflight mission. The Indian Space Research Organisation, which expects to conduct the first crewed flight under this mission no earlier than 2026, paid more than ₹500 crore for the Ax-4 mission to include Mr. Shukla and Prasanth Nair, another Gaganyaan designate who was part of the back-up crew for the Ax-4 mission.

Mission update: Shubhanshu Shukla and his fellow astronauts being welcomed aboard by the ISS crew. PTI

On Thursday's flight, Mr. Shukla was the mission pilot. A live videolink from NASA showed the spacecraft approaching the station, with the docking sequence being completed at 4.15 p.m.

At the lift-off on Wednesday evening from Florida, Axiom Space – which is orchestrating the mission – had said the capsule would attempt docking in about 28 hours.

"Shubhanshu stands at the threshold entrance of International Space Station... as the world watches with excitement and expectation," Union Minister of State for Space Jitendra Singh wrote in a post on X.

The four astronauts aboard will spend the next two weeks at the ISS conducting scientific experiments, including eight from ISRO, and helping with the station's upkeep.

The first delay was due to adverse weather, followed by technical issues in the Falcon 9 rocket and then on the ISS.

In the lead-up to the Ax-4 mission, both Mr. Shukla and Mr. Nair had received advanced training at NASA's Johnson Space Centre in Texas.

Along with the other Gaganyaan designates Ajit Krishnan and Angad Pratap, they had previously received training in Russia. Training inputs from the U.S. and Russia are deemed valuable because of their considerable human spaceflight experience.

मुख्य बिंदु:

1. **ISS में ऐतिहासिक प्रवेश:**
   - शुक्ला ने Axiom Space द्वारा प्रक्षेपित ड्रैगन क्रू कैप्सूल में सवार होकर ISS तक की यात्रा की, जिसका डॉकिंग उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर हुआ।
   - उन्होंने "स्पेस से नमस्कार" कहकर देश को संबोधित किया, जो राष्ट्रीय गर्व का प्रतीकात्मक क्षण था।
   - वह ISS पर दो सप्ताह बिताएंगे, जहाँ वे वैज्ञानिक प्रयोग और रखरखाव गतिविधियों में भाग लेंगे।
2. **गगनयान के लिए महत्त्व:**
   - शुक्ला भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए नामित चार अंतरिक्षयात्रियों में से एक हैं, जिसकी संभावना 2026 के आसपास है।
   - Ax-4 में उनकी भागीदारी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान संचालन में भारत की रणनीतिक तैयारी और अनुभव का हिस्सा है।
3. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
   - इस भागीदारी के लिए भारत ने ₹500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, जो उन्नत अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए ISRO की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
   - प्रशिक्षण NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर (अमेरिका) और रूस में प्राप्त किया गया, जो मानव अंतरिक्ष उड़ानों के अनुभव में समृद्ध हैं।
   - बैकअप क्रू सदस्य प्रशांत नायर ने भी यह प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे मिशन की तैयारी सुनिश्चित हुई।
4. **वैज्ञानिक और तकनीकी प्रासंगिकता:**
   - ISRO के आठ वैज्ञानिक प्रयोग ISS मिशन का हिस्सा हैं, जो भारत की सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और मानव शरीर विज्ञान में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
   - यह मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोटोकॉल का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, जिससे भारत की स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणाली को बल मिलता है।
5. **मिशन की चुनौतियाँ और लचीलापन:**
   - लॉन्च में कई बार देरी हुई — पहले मौसम के कारण, फिर फाल्कन 9 रॉकेट में तकनीकी समस्याओं के कारण, और बाद में ISS पर।
   - इसके बावजूद सफल डॉकिंग और मिशन की शुरुआत भारत की अंतरिक्ष सहभागिता में लचीलापन और परिपक्वता को दर्शाती है।

भारत के लिए प्रभाव:

1. **रणनीतिक और तकनीकी छलांग:**
   - यह भारत की मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारत की क्षमता को सुदृढ़ करता है।

2. **गगनयान की तैयारी को बढ़ावा:**
   - ISS संचालन का वास्तविक अनुभव गगनयान अंतरिक्षयात्रियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मिशन सिमुलेशन को मजबूती देता है।
   - यह दिखाता है कि ISRO घरेलू क्षमताओं को वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ संयोजित कर रहा है।
3. **सॉफ्ट पावर और कूटनीति:**
   - यह वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है।
   - अमेरिका और रूस की निजी व सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग से भारत की अंतरिक्ष कूटनीति को बल मिलता है।
4. **प्रेरणा और क्षमता निर्माण:**
   - यह अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि है।
   - यह STEM शिक्षा, अनुसंधान और भारत में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

शुभांशु शुक्ला का ISS में प्रवेश केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक रणनीतिक सफलता है। यह देश की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं का एक निर्णायक क्षण है और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग और इस मिशन के माध्यम से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव गगनयान और भविष्य के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए लॉन्चपैड का कार्य करेगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ता है।" एक्सिओम मिशन 4 में भारत की भागीदारी के सामरिक, तकनीकी और कूटनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करें। **(250 words)**

Page : 05 : GS 2 : Indian Polity

प्रस्तावित संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति को अपनी लिखित प्रस्तुति में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह राय व्यक्त की है कि चक्रीय (विखंडित) चुनाव संविधान की कोई अपरिवर्तनीय विशेषता नहीं हैं। उनका यह मत ऐसे समय में आया है जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता और उपयुक्तता को लेकर व्यापक बहस चल रही है।

Staggered polls cannot be considered an immutable feature of Constitution: ex-CJI

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Conducting free and fair elections is a basic feature of the Constitution, but the Constitution does not say that polls can be free and fair only if they are held non-simultaneously, former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has opined, according to sources, in his written submission to the Parliamentary Joint Committee reviewing the proposed legislation aiming to introduce simultaneous elections.

Justice Chandrachud, who served as the CJI from November 2022 to November 2024, will present his views to the panel on July 11. Justice J.S. Kehar, who served as CJI between January and August 2017, has also been invited by the panel, which is reviewing the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024.

Former CJI D.Y. Chandrachud will present his views on simultaneous elections to a Parliamentary Joint Committee on July 11. PTI

Their predecessors who had met the panel earlier had pointed out several infirmities in the legislation, according to sources.

Justice Chandrachud, as per sources, has dismissed the contention that holding simultaneous elections would blur the distinction between different tiers of government, since voters may prioritise national issues over regional concerns if the election cycles are synchronised. This argument, he said, is based on the assumption that the Indian electorate is "naive" and can be easily "manipulated". This contention, he has argued, flies in the face of the universal adult franchise which has been part of the Constitution since its inception.

He further said in his submission, as per sources, that "staggered elections cannot be considered as a feature of the original Constitution, let alone an immutable feature."

According to sources, he has also referred to the concern that simultaneous elections could marginalise smaller parties or regional parties. But this problem, he said, exists independent and irrespective of the simultaneous election legislation.

प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु:

1. **मुक्त और निष्पक्ष चुनाव – एक मौलिक विशेषता, न कि चक्रीय चुनाव:**
    - न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की एक मूलभूत विशेषता हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया कि गैर-समानता (अर्थात् अलग-अलग समय पर चुनाव) कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है।

- उन्होंने तर्क दिया कि संविधान में ऐसा कोई पाठ्य या संरचनात्मक आधार नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव चक्रीय रूप से ही कराए जाएं।

2. **मतदाताओं की चुनावी परिपक्वता:**
    - उन्होंने इस चिंता को खारिज किया कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच अंतर धुंधला हो जाएगा।
    - उनका कहना था कि यह मानना कि मतदाता विभिन्न स्तरों की सरकारों में अंतर नहीं कर सकते, भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता को कम करके आंकना है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का निरंतर अभ्यास किया है।
3. **न तो मूलभूत और न ही अपरिवर्तनीय संवैधानिक विशेषता:**
    - उन्होंने कहा कि चक्रीय चुनाव संविधान का कोई मूल या स्थायी हिस्सा नहीं थे।
    - वर्तमान में चक्रीय चुनाव प्रणाली मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाक्रमों (जैसे – विधानसभाओं का समयपूर्व विघटन) का परिणाम है, न कि किसी सोच-समझकर बनाई गई संवैधानिक योजना का।
4. **छोटे और क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव:**
    - यह चिंता व्यक्त की गई थी कि एक साथ चुनाव छोटे या क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर धकेल सकते हैं।
    - न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यह समस्या चुनाव की समय-सीमा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, इसलिए इसे इस प्रस्ताव के विरोध का वैध आधार नहीं माना जा सकता।

इस दृष्टिकोण का महत्व:

- **संविधान की संतुलित व्याख्या:**
    - पूर्व CJI का दृष्टिकोण एक परिपक्व और संवैधानिक सोच प्रस्तुत करता है, जो चुनावी शुचिता और व्यावहारिक शासन के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- **एक साथ चुनावों के लिए वैधानिक आधार को मजबूती:**
    - उनका मत इस विचार को बौद्धिक और कानूनी समर्थन प्रदान करता है कि एक साथ चुनाव संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते, जिससे विधायी सुधार के मार्ग में एक प्रमुख बाधा दूर होती है।
- **मतदाताओं में लोकतांत्रिक विश्वास:**
    - यह मतदाताओं की गरिमा और उनकी विवेकशीलता पर विश्वास व्यक्त करता है, यह मानते हुए कि लोकतंत्र एक जागरूक और सक्षम नागरिकता पर आधारित है, न कि एक भ्रामक या प्रभावित की गई जनता पर।

अब भी मौजूद चुनौतियाँ:

- **लॉजिस्टिक और प्रशासनिक जटिलताएँ:**
    - इतने विशाल और विविध देश में एक साथ चुनाव कराना बड़े संस्थागत पुनर्गठन, कार्यकालों का समन्वय और संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता रखता है।

- **राजनीतिक सहमति:**
    - इस सुधार की सफलता व्यापक राजनीतिक सहमति पर निर्भर करती है, जो अभी भी साकार नहीं हो सकी है, विशेषकर क्षेत्रीय दलों के विरोध के कारण जो अपनी विशिष्ट पहचान के खोने का डर रखते हैं।

निष्कर्ष:

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की यह स्पष्टता "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर बहस को संवैधानिक दृष्टिकोण से पुनः प्रासंगिक बनाती है। जबकि लॉजिस्टिक और राजनीतिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, उनका यह कथन कि चक्रीय चुनाव कोई पवित्र विशेषता नहीं हैं, इस विचार पर गंभीर विधायी और कानूनी विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक दक्षता आती है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।" हाल ही में विशेषज्ञों की राय के आलोक में, भारत में एक साथ चुनाव कराने के संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थों की आलोचनात्मक जाँच करें। **(250 Words)**

Page 07 : GS 2 : International Relations

बैंकॉक में आयोजित नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (CRVS) पर तीसरे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सरकारों ने 2030 तक जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। यह संयुक्त राष्ट्र के UNESCAP द्वारा संचालित "CRVS दशक" (2014–2024) की एक दशक लंबी पहल के बाद हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन सार्वभौमिक कवरेज में कुछ खामियाँ शेष रहीं।

At Bangkok event, a commitment to count every birth and death

Governments across Asia and the Pacific decide to ensure registration of all vital events of the population by 2030; an estimated 14 million children in the region still do not have their births registered by their first birthday and every year, an approximate 6.9 million deaths go unrecorded

Ramya Kannan

Governments across Asia and the Pacific, on Thursday, signed off on a landmark decision to ensure that all births are registered and all deaths are recorded by 2030, at the third Ministerial conference on Civil Registration and Vital Statistics for Asia and the Pacific, in Bangkok, Thailand. This is expected to bring the vison of universal, inclusive and resilient CRVS systems a step closer to reality.

The United Nations defines civil registration and vital statistics as the "continuous, permanent, compulsory and universal recording of the occurrence and characteristics of vital events of the population in accordance with the law".

What are the vital events?

These vital events include births, deaths and marriages, divorces, besides causes of death. The focus of the nations is on registering births and deaths as a fundamental aspect of a person's legal identity, and besides, grant access to a whole range of life-cycle benefits/functions for any one living in a society. Birth registration grants individuals formal legal recognition, enabling access to essential rights and services, including health services. Death certificates serve as legal proof of death, supporting families with matters such as inheritance, insurance and other administrative processes.

In 2014, the United Nations' Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), launched the "CRVS Decade" to 'Get every one in the picture.' The decadal progress was measured in a review that was then launched as a publication last week.

In her preface to the publication, Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, wrote: "Importantly, civil registration and vital statistics (CRVS) systems help protect populations in vulnerable situations, as birth and marriage registration can serve as safeguards against child marriage, trafficking and modern slavery by verifying age and identity."

Acknowledging legal identity in good governance and justice, is also target 16.9 of the Sustainable Development Goals (SDGs). Birth registration has an intergenerational impact, empowering registered mothers to secure legal identity and rights for their children, breaking cycles of invisibility and exclusion.

Earlier, speaking to presspersons, Ms. Alisjahbana said the ID card is the most important part of every one's wallet, and as such it goes beyond a mere document. There have been accelerated actions by many countries that have led to better registration rates in these nations, and the successes have come as a result of collaborative work in the region and learning from each other's work.

As a result, over the past decade, in the countries in the Asia Pacific region, the number of children under five who are unregistered had dropped from 135 million in 2012 to 51 million, a reduction of more than 60%. 29 countries currently have reported over 90% registration of births in a year, and 30 countries have achieved this for death registration. The quality of cause of death reporting has also significantly improved, the ESCAP acknowledged.

However, despite this progress, an estimated 14 million children across the region still do not have their births registered by their first birthday. Every year, an approximate 6.9 million deaths also go unrecorded.

Planning ahead: The third Ministerial conference on Civil Registration and Vital Statistics for Asia and the Pacific was held in Bangkok, Thailand. X/@UNESCAP

Extension of deadline

Responding to a question on the future of the programme, Ms. Alisjahbana said: "We have been very fortunate in seeing significant progress, and political will and investments in this decade. They have paid off. But there is a lot of work to be done yet, and there is in place a very good momentum to accelerate operations and digitalisation to ensure registration. So the consensus among member nations is to extend it to 2030."

With the chosen decade complete, but 100% registration still not achieved, the Declaration has decided to extend the roadmap to 2030, the end of the decade, with people at the centre. It calls for inclusive and accessible service delivery, harnessing the power of digital transformation, strengthening legal foundations and building inter-operable data systems. The governments also provided commitments to ensuring gender equity in registration, safeguarding personal data and privacy.

Indian scenario

In India, the Registrar-General and Census Commissioner is responsible for civil registration as well as the production of vital statistics. The Ministry of Health supports the civil registration system providing incentives for registration, manpower and logistics support under the National Health Mission. There is no fee for birth registration within the prescribed period of 21 days, although fees for birth certificates may vary according to State/local body.

The Indian national CRVS coordination mechanism was established in August 2015, while a national CRVS strategy and a comprehensive assessment are still in progress. In 2011, the Office of the Registrar-General identified challenges such as lack of awareness regarding the need and importance of registration, low priority accorded to the system of civil registration by the States, lack of coordination among the concerned departments and low level of reporting by registration units.

> Civil registration and vital statistics systems help protect populations in vulnerable situations, as birth and marriage registration can serve as safeguards against child marriage, trafficking and modern slavery by verifying age and identity
>
> **ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA**
> Under-Secretary-General, UN

To tackle these issues, several initiatives were launched. Among these measures were developing a software application for online and offline registration of birth and death covering the entire gamut of the civil registration system: registration of events, generation of certificates, and generation of statistical tables and reports. In addition, a new project on data digitisation is being implemented, with the support of UNICEF, to keep old records in easy to retrieve digital form has started. This will help in storage of registers in electronic format and allow easy access to the records.

Digital transformation

Ms. Alisjahbana earlier acknowledged this, in response to a question from *The Hindu*, that India with its strength and leadership in digital transformation has helped a lot with rolling out a CRVS system that can be implemented digitally. Tanja Sejersen, Statistician, ESCAP, who spoke to presspersons, along with Ms. Alishjahbana, said, the use of technology has been super helpful in certain countries in advancing the principle of registration, but in other countries, could be a stumbling block. There has been, since the launch of the decade of CRVS, a broader push for linking digital transformation. India's representative at the Ministerial conference, Nityanand Rai, Minister of State, Ministry of Home Affairs, said the country has embarked an citizen-centric activities that will make universal registration possible across the country. The registration of births and deaths is mandatory under the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969, and amendments to it, have made possible digital registration of births and deaths and the recognition of electronic documents that can be stored safely and securely in the Digilocker by all, obviating the need for presenting hard copies of documents.

In India, legal provisions now cover the registration of adopted, orphaned, abandoned, surrendered, and surrogate children, along with children of single parents or unmarried mothers. It has been made mandatory for medical institutions to provide cause of death certificates to the Registrar. He added that a new central CRVS portal had been launched too. As a result of these proactive policies, the registration of births had increased from just over 86% at the beginning of the CRVS decade to over 96% in India, he said.

Children participants at the Ministerial conference made a strong pitch for ensuring registration for all children irrespective of the many variables that may make it difficult for their parents to register their births. "Bureaucracy shouldn't be the reason we remain invisible," they said.

As the conference wound to a conclusion, the nations' commitments seemed solid. If commitments count, then strident steps had already been made towards achieving universal registration in the Asia and Pacific region. The words of Siromi Turaga, Minister for Justice and Acting Attorney General, Fiji, during his address at the Ministerial event, must go home though, to every nation: "The progress of the decade was only possible because of shared commitment in the region. As we look ahead to 2030...together we can ensure that every person in our region is seen heard and counted."

(This reporter was at Bangkok at the invitation of UN-ESCAP)
(ramya.kannan@thehindu.co.in)

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु:

1. **नवीन प्रतिबद्धता:**
    - घोषणा में CRVS पहल को 2030 तक बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण हासिल करना है।
    - समावेशी, डिजिटल और पारस्परिक रूप से संगत (interoperable) CRVS प्रणालियों के निर्माण पर ज़ोर।
    - पंजीकरण के माध्यम से लैंगिक समानता, डेटा गोपनीयता और कानूनी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई।
2. **वर्तमान खामियाँ:**
    - प्रगति के बावजूद, 1 वर्ष की आयु तक के 1.4 करोड़ बच्चे अब भी पंजीकृत नहीं हैं।
    - हर साल लगभग 69 लाख मौतें क्षेत्र में बिना पंजीकरण के रह जाती हैं।
    - केवल 29 देशों ने ही 90% से अधिक जन्म पंजीकरण हासिल किया है, और 30 देशों ने मृत्यु पंजीकरण में यह स्तर प्राप्त किया है।
3. **CRVS की व्यापक महत्ता:**
    - जन्म पंजीकरण कानूनी पहचान की कुंजी है, जो अधिकारों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक लाभों की पहुँच के लिए आवश्यक है।
    - मृत्यु पंजीकरण कानूनी प्रक्रिया को पूर्णता देता है, जिससे उत्तराधिकार, बीमा और जनस्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
    - CRVS बाल विवाह, मानव तस्करी और गुलामी के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यह उम्र और पहचान की पुष्टि करता है।
4. **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंध:**
    - यह सीधे SDG लक्ष्य 16.9 से जुड़ा है: सभी के लिए कानूनी पहचान, जिसमें जन्म पंजीकरण भी शामिल है।
    - यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों से भी संबंधित है।

भारत की प्रगति और भूमिका:

1. **उपलब्धियाँ:**
    - भारत ने CRVS दशक के दौरान जन्म पंजीकरण को 86% से बढ़ाकर 96% से अधिक कर लिया है।
    - मृत्यु पंजीकरण और मृत्यु के कारणों का दस्तावेजीकरण भी कानूनी प्रावधानों और डिजिटलीकरण के कारण बेहतर हुआ है।
2. **नीतिगत और कानूनी ढाँचा:**
    - यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा शासित है, जिसे हाल ही में संशोधित कर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण और डिजीलॉकर में संग्रह की अनुमति दी गई है।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं ताकि पंजीकरण और डेटा एकीकरण निर्बाध रूप से हो सके।
- अब यह कानून गोद लिए गए, सरोगेसी, अनाथ और परित्यक्त बच्चों, और अविवाहित माता-पिता के मामलों को भी कवर करता है।

3. **पहचानी गई चुनौतियाँ:**
   - जन-जागरूकता की कमी, राज्यों द्वारा प्राथमिकता की कमी, विभागों के बीच समन्वय का अभाव, और अधोसंरचना की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं।
   - वास्तविक समय के डेटा सिस्टम, गोपनीयता सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
4. **डिजिटल नेतृत्व:**
   - भारत की डिजिटल प्रणाली (आधार, डिजीलॉकर, CRVS पोर्टल) को क्षेत्र में नागरिक-केंद्रित, स्केलेबल डिजिटल CRVS सिस्टम के मॉडल के रूप में मान्यता मिल रही है।

क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व:

- यह पहल मानव अधिकारों, पहचान और डेटा न्याय पर एक प्रमुख अंतर-सरकारी सहमति को दर्शाती है।
- विभागों और सीमाओं के पार तकनीक-सक्षम शासन और इंटरऑपरेबिलिटी पर बल।
- विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के लिए मानव-केंद्रित विकास दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है।

निष्कर्ष:

बैंकॉक सम्मेलन 2030 तक समावेशी, लचीले और जन-केंद्रित CRVS सिस्टम बनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का एक निर्णायक पुन: पुष्टिकरण है। भारत के लिए यह एक स्वीकृति का क्षण भी है और गहराई से कार्रवाई करने का आह्वान भी — विशेषकर डेटा सटीकता, अंतिम छोर तक सेवा पहुँच, और गोपनीयता की सुरक्षा के क्षेत्र में। जैसे-जैसे क्षेत्र आगे बढ़ेगा, साझा अनुभव और डिजिटल नवाचार यह सुनिश्चित करने की कुंजी होंगे कि हर व्यक्ति को देखा जाए, सुना जाए और गिना जाए।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "नागरिक पंजीकरण और जीवन सांख्यिकी (सीआरवीएस) समावेशी विकास और कानूनी सशक्तीकरण के लिए केंद्रीय है।" भारत की प्रगति और एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय प्रयासों के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 Words)**

Page : 10 : GS 1 : Art & Culture

पुरातत्वविद् के. अमरनाथ रामकृष्ण का तबादला और केीलाड़ी खुदाई पर रिपोर्ट संशोधित करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का निर्देश एक बार फिर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस को जन्म दे चुका है। संगम युग के एक शहरी स्थल के रूप में केीलाड़ी, तमिल गौरव और प्राचीन सभ्यता की पहचान का प्रतीक बन गया है। यह विवाद वैज्ञानिक प्रमाणिकता, सांस्कृतिक विरासत की मान्यता, और ASI की कार्रवाई के पीछे संभावित राजनीतिक उद्देश्यों के इर्द-गिर्द घूमता है।

What sparked the Keeladi controversy?

What was the dispute between the archaeologist and the ASI? Why did the ASI ask for a rewrite of the Keeladi report? Why did political parties react strongly to the decision? How did the public and historians respond to the findings?

EXPLAINER

D. Suresh Kumar

The story so far:

On June 17, archaeologist K. Amarnath Ramakrishna, whose excavation at Keeladi in Tamil Nadu drew the nation's attention, was transferred yet again, this time from New Delhi to Greater Noida. Mr. Ramakrishna, who was serving as the Director (Antiquity) and as Director of the National Mission on Monuments and Antiquities (NMMA), will now be the Director of the NMMA only. The NMMA unit, set up in 2007, according to sources, remains almost defunct. Over two years after Mr. Ramakrishna submitted his 982-page report on the first two phases of excavations carried out at Keeladi between 2014 and 2016, a fresh controversy erupted last month. The Archaeological Survey of India (ASI) mandated that he revise his report, but he refused to do it. This disagreement sparked a political clash between the Centre and Tamil Nadu.

How did Keeladi excavation begin?

Keeladi has become a symbol of pride for many in Tamil Nadu. Over a decade ago, Amarnath Ramakrishna, then the ASI's Superintending Archaeologist, had initiated excavations at a site known as the Pallichanthai Tidal in Keeladi, originally a coconut grove spanning 100 acres. He had identified over 100 sites for excavation along the Vaigai River, but Keeladi stood out.

It was in Keeladi that they unearthed over 7,500 ancient artifacts, including wall structures, drainage systems, and wells – all evidence of a sophisticated urban society that thrived. What was even more compelling was the carbon dating, which revealed that these elements are over 2,160 years old, dating back to the 2nd century BCE, which is the time of the Sangam period in Tamil history.

K. Amarnath Ramakrishna at the Keeladi excavation site. FILE PHOTO

What made the findings significant?

Archaeologists were stunned by a few findings. Most importantly, there was no evidence of religious symbols at the excavation site, which hinted at the secular nature of the civilisation.

So, naturally, the excitement around Keeladi's discoveries was palpable. Tamil historians and enthusiasts saw it as proof of an advanced ancient Tamil civilisation, but soon after, things took a sharp turn.

What did political critics accuse the Centre of doing?

It all began in 2017, when the ASI transferred Mr. Ramakrishna to Assam just as the excavations were ramping up after the first two phases. Back then, political critics accused the Centre of deliberately derailing the excavations. It is because the Centre that had promised funding and support for further digs delayed both after the second phase.

The local political climate grew tense with some alleging that the Centre was trying to suppress Tamil heritage. By 2017, the excavations had entered its third phase, this time, under archaeologist P.S. Sriraman. After excavating just around 400 square meters, he reported a lack of continuity in the brick structures previously discovered.

Did State's findings resolve the issue?

The Madras High Court stepped in, with judges visiting the excavation site. The court then directed the ASI to continue the excavations and allowed the Tamil Nadu State Department of Archaeology to get involved. The department, in 2019, published a report asserting that Keeladi was an urban settlement dating back to the Sangam era between the 6th century BCE and the 1st century CE.

Since the third phase, the State Archaeology Department has continued the project, but these findings have not helped resolve the issue; instead, the drama has escalated. In January 2023, Mr. Ramakrishna, who was transferred back to Tamil Nadu, submitted his report on the first two phases of excavation.

What did the ASI ask Ramakrishna to do with the report?

For about two-and-a-half years, this report remained with the ASI, and just last month, the ASI sent Mr. Ramakrishna a letter to revise the report. The ASI questioned the dating and depth of certain findings, suggesting the evidence for the earliest period, as it "appeared to be very early," and said it needed further analysis. Mr. Ramakrishna, however, stood firm and refused to rewrite his conclusions, defending his work as scientifically sound, based on rigorous archaeological standards. He argued that the report's chronology was backed by stratigraphic sequences, material culture and even Accelerator Mass Spectrometry.

Why did the ASI's decision spark political outrage?

Against this backdrop, many political parties in Tamil Nadu have slammed the ASI's decision. They have termed it a blatant attempt to suppress Tamil heritage. They argued that the Centre's refusal to acknowledge Keeladi's significance was not just about science but also about politics. Amid the backlash, the Union Minister for Culture, Gajendra Singh Shekhawat, said Mr. Ramakrishna's findings were not technically well-supported and further scientific studies were required to validate the findings. He sought more results, data, and evidence because he said a single finding cannot change the entire discourse.

Why did AIADMK stay silent initially?

Interestingly, the AIADMK, which was in power when the Keeladi report was published, remained silent for a long time on the current controversy. However, on June 18, senior leader R.B. Udhayakumar contended that the Centre had sought more information by way of ensuring "additional corroboration." He also said, "if the Keeladi report is rejected, the AIADMK will be the first party to express its voice of protest."

The controversy is not just about one report or one excavation; it is a clash of narratives. The Centre insists on scientific validation while Tamil Nadu views it as a matter of historical recognition. The State government is pressing on with its excavations, which are under way, and it has already set up a new museum at Keeladi, drawing thousands of visitors.

THE GIST

- Archaeologist Amarnath Ramakrishna's transfer from New Delhi to Greater Noida and the ASI's demand to revise his 982-page Keeladi excavation report sparked renewed controversy.
- The ASI questioned the dating and depth of the findings, but Ramakrishna defended his conclusions as scientifically sound, citing stratigraphy and Accelerator Mass Spectrometry.
- The move drew political outrage in Tamil Nadu, with parties accusing the Centre of suppressing Tamil heritage, turning Keeladi into a flashpoint between science, politics, and identity.

विवाद कैसे शुरू हुआ:

1. **खुदाई और महत्व:**

- वैगई नदी के पास स्थित केीलाड़ी में 7,500 से अधिक पुरावशेष मिले, जिनमें शहरी संरचनाएं (जल निकासी प्रणाली, ईंटों की इमारतें) शामिल हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं।
- कार्बन डेटिंग ने इन खोजों को संगम युग में रखा, जिससे यह धारणा चुनौती में आ गई कि भारत में उन्नत शहरी जीवन मुख्यतः उत्तर भारतीय और आर्य परंपरा से जुड़ा हुआ था।

2. **धार्मिक प्रतीकों की अनुपस्थिति:**
   - मंदिरों या मूर्तिकला जैसे धार्मिक चिन्हों की अनुपस्थिति ने समाज की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की ओर संकेत किया, जिससे प्रारंभिक तमिल संस्कृति और शासन के बारे में नए दृष्टिकोण सामने आए।

टकराव के बिंदु:

1. **ASI का विरोध:**
   - ASI ने रामकृष्ण की 982-पृष्ठीय रिपोर्ट में कालक्रम और निष्कर्षों पर सवाल उठाए और संशोधन की मांग की।
   - रिपोर्ट पर लंबे समय तक चुप्पी और फिर संशोधन की मांग को स्थल के महत्व को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे जन और राजनीतिक आक्रोश उत्पन्न हुआ।
2. **रामकृष्ण का प्रतिरोध:**
   - उन्होंने अपनी रिपोर्ट को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक बताया, जो भूस्तरीय क्रम (stratigraphy), सांस्कृतिक परतों और AMS (एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री) डेटिंग तकनीक पर आधारित थी।
   - उन्होंने दबाव में आकर रिपोर्ट बदलने से इनकार कर दिया और इसे अपनी अकादमिक और व्यावसायिक ईमानदारी का विषय बताया।

राजनीतिक आयाम:

1. **केंद्र-राज्य टकराव:**
   - तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों (विशेष रूप से DMK आदि) ने केंद्र पर द्रविड़ विरासत को दबाने का आरोप लगाया।
   - AIADMK, जो प्रारंभ में चुप थी, ने बाद में संकेत दिया कि अगर केंद्र रिपोर्ट को खारिज करता है तो वह विरोध में आवाज उठाएगी।
2. **केंद्र सरकार का पक्ष:**
   - उसने कहा कि ऐतिहासिक कथाओं को संशोधित करने से पहले और अधिक प्रमाण और पुष्टिकरण की आवश्यकता है।
   - संस्कृति मंत्री ने कहा कि किसी भी निष्कर्ष की स्वीकृति क्षेत्रीय भावना के बजाय वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए।

जनता और विद्वानों की प्रतिक्रिया:

- इतिहासकारों और नागरिक समाज समूहों ने पुरातात्विक विज्ञान में नौकरशाही हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई।

- केीलाड़ी तमिल पहचान का प्रतीक बन गया, जिससे खुदाई को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला और एक संग्रहालय की स्थापना हुई।
- यह मुद्दा सांस्कृतिक संघवाद का बिंदु बन गया, जहाँ राज्य ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को केंद्र की उपेक्षा के विरुद्ध सामने रखा।

प्रशासनिक और नैतिक मुद्दे:

- यह शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता, अनुसंधान की स्वतंत्रता, और ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में प्रमाण बनाम विचारधारा की भूमिका जैसे प्रश्नों को उठाता है।
- यह क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय इतिहास कथाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

केीलाड़ी विवाद केवल पुरातात्विक खोजों का विषय नहीं है — यह इतिहास, पहचान और सत्ता के बीच गहरे संघर्ष को दर्शाता है। जहाँ वैज्ञानिक कठोरता आवश्यक है, वहीं पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया के बिना वैध अनुसंधान को कमजोर करना संस्थागत विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "कीलाडी उत्खनन ने वैज्ञानिक जांच को राजनीतिक और सांस्कृतिक आख्यानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौतियों को उजागर किया है।" भारत में विरासत प्रबंधन और केंद्र-राज्य गतिशीलता के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 words)**

Page : 08 Editorial Analysis

Fathoming America's plan to manage AI proliferation

Rijesh Panicker
is a Fellow at the Takshashila Institution

Bharath Reddy
is an Associate Fellow at the Takshashila Institution

Ashwin Prasad
is a Research Analyst at the Takshashila Institution

The announcement by the United States of the rescission of its Framework for AI Diffusion, a set of export controls for Artificial Intelligence (AI) technology announced earlier this year, has been viewed as a good thing. The Framework was considered counterproductive to AI technology development and diplomatic relations. However, recent developments suggest that controls on AI are likely to persist, albeit in different forms.

A flawed blueprint

Earlier this year, during the final week of its tenure, the Joe Biden administration announced the AI Diffusion Framework. Combining export controls and export licences for AI chips and model weights, it effectively viewed AI like nuclear weapons. Under the proposed framework, countries such as China and Russia were embargoed, trusted allies were favoured, and others restricted in their access to advanced AI technology. The rationale for these rules was that computational power dictates AI capabilities: the greater the compute, the better the AI. In the last decade, the compute used in advanced AI models has nearly doubled every 10 months. Following this logic, for the U.S. to preserve its lead, it needed to prevent adversaries from acquiring powerful compute while ensuring that AI development stays within the U.S. and its close allies.

While export controls on AI hardware predated the framework, they were not sweeping. The Framework aimed to tighten these controls and establish a predictable system to streamline regulatory processes and standardise conditions. However, imposing such sweeping restrictions, affecting adversaries and partners alike, brought many unintended effects, proving counterproductive.

The framework set a concerning precedent for technology cooperation with the U.S., especially for its allies. It signalled U.S. willingness to dictate how other nations conducted their affairs, incentivising them to hedge against U.S. actions. Consequently, U.S. allies had reasons to invest in alternatives to the U.S. ecosystem, pursuing their own strategic autonomy and technological sovereignty.

> The rescission of the AI Diffusion Framework appears to be more a change in tactics than a fundamental shift in strategy

Additionally, the framework would treat AI, a civilian technology with military applications, as if it were a military technology with civilian uses. Unlike nuclear technology, AI innovation is inherently civilian in its origins and international in scope. Confining the development geographically within the U.S. could prove counterproductive.

Finally, the system created an enduring incentive for the global scientific ecosystem to develop pathways to circumvent the need for powerful compute to make powerful AI, thereby undermining the very lever that the U.S. sought to employ. China's DeepSeek R1 exemplifies this. Years of export controls spurred algorithmic and architectural breakthroughs, enabling DeepSeek to rival the best AI models from the U.S. with a fraction of the compute. Such trends can make export controls on AI chips an ineffective policy instrument.

It is for these reasons that the Trump administration revoked the AI Diffusion Framework. This is welcome news for India, which was not favourably placed under the framework. However, the underlying U.S. thinking and approach towards AI diffusion will likely persist, manifesting in other forms. The AI technology race is still on, and the U.S. intent to restrict Chinese access to AI chips still endures.

The possible replacement

Notwithstanding the rescinded Framework, the current U.S. administration has taken firm steps toward further preventing Chinese access to AI chips. For instance, in March 2025, the administration expanded the scope of the existing export controls and added several companies to its entity list (blacklist). It has also released several new guidelines to strengthen the enforcement of these controls.

New provisions are reportedly under consideration, such as on-chip features to monitor and restrict the usage of AI chips. These could include rules at the hardware level limiting chip functionality or restricting certain use cases. Recently, U.S. lawmakers introduced new legislation mandating built-in location tracking for AI chips to prevent their illicit diversion into China, Russia and other countries of concern. In effect, these measures seek to enforce the goals of the AI diffusion framework technologically rather than through trade restrictions.

The related concerns

Such measures are problematic in their own way. New concerns related to ownership, privacy and surveillance will proliferate. While malicious actors might be sufficiently motivated to circumvent these controls, legitimate and beneficial use by others could be inadvertently discouraged. Such developments undermine user autonomy and lead to trust deficits. Just like the old framework, this will lead to concerns about losing strategic autonomy for any nation buying AI chips. Yet again, both adversaries and allies will feel compelled to hedge against their reliance on the U.S. AI ecosystem and invest in alternatives.

The rescission of the AI Diffusion Framework represents a notable policy reversal. Yet, it appears to be more a change in tactics than a fundamental shift in the U.S. strategy to manage AI proliferation. Should these technologically-driven control measures gain traction in U.S. policy discourse and be implemented, they risk replicating the negative consequences of the original AI Diffusion Framework. Ultimately, should this path be pursued, it would indicate that the crucial lessons from the Framework and its eventual withdrawal have not been fully assimilated, potentially jeopardising the very U.S. leadership in AI it ostensibly seeks to protect.

Paper 03 : Science & Technology

UPSC Mains Practice Question : अमेरिका द्वारा एआई प्रसार ढांचे को वापस लेना एक सामरिक बदलाव है, न कि कोई रणनीतिक बदलाव। वैश्विक तकनीकी शासन और भारत की एआई कूटनीति के आलोक में इस कथन की जाँच करें। (250 words)

Context :

संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को वापस ले लिया है — यह नीति विशेष रूप से चीन और रूस जैसे शत्रुत्वपूर्ण देशों की दिशा में उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के वैश्विक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह वापसी अमेरिकी नीति में नरमी के संकेत के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन गहन विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिबंधात्मक उपाय संभवतः जारी रहेंगे, हालांकि अब वे प्रत्यक्ष व्यापार नियंत्रणों की बजाय तकनीकी रूप से एम्बेडेड रूपों में होंगे।

फ्रेमवर्क की पृष्ठभूमि:

- **AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क** बाइडेन प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य AI चिप्स और मॉडल वेट्स के लिए एक निर्यात नियंत्रण तंत्र बनाना था, इन्हें सैन्य-ग्रेड या परमाणु प्रौद्योगिकियों के समान माना गया।
- इसका उद्देश्य **AI कंप्यूट शक्ति** को शत्रुओं तक पहुँचने से रोकना और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के बीच तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करना था।
- हालांकि, इस फ्रेमवर्क को अत्यधिक व्यापक, प्रतिकूल और कूटनीतिक रूप से नुकसानदायक मानकर आलोचना का सामना करना पड़ा — यहाँ तक कि सहयोगी देशों द्वारा भी।

मुख्य मुद्दे और आलोचनाएँ:

1. **रणनीतिक अतिक्रमण (Strategic Overreach):**
    - यह फ्रेमवर्क संकेत देता है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर तकनीकी उपयोग की शर्तें निर्धारित करना चाहता है, जिससे साझेदारों और शत्रुओं — दोनों के बीच असहजता उत्पन्न हुई।
    - इससे **विश्वास की कमी** पैदा हुई और अन्य देशों को रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
2. **AI की गलत व्याख्या:**
    - AI को सैन्य-प्रथम प्रौद्योगिकी मानना उसके **मुख्यतः नागरिक मूल और वैश्विक नवाचार नेटवर्क** की अनदेखी करता है।
    - इसे परमाणु तकनीक से तुलना करना अनुचित है क्योंकि AI एक **लोकतांत्रिक और तेजी से विकसित हो रही** तकनीक है।

3. **प्रतिकूल नवाचार (Counterproductive Innovation):**
    - निर्यात नियंत्रणों ने चीन जैसे देशों को **कम कंप्यूट पर आधारित AI मॉडल** विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
    - उदाहरण: **DeepSeek R1**, एक शक्तिशाली चीनी मॉडल है जो बहुत कम कंप्यूट का उपयोग करता है, जिससे कंप्यूट-आधारित प्रतिबंधों की रणनीति कमजोर हो गई।
4. **भारत और वैश्विक दक्षिण पर प्रभाव:**
    - भारत को इस फ्रेमवर्क में अनुकूल स्थिति में नहीं रखा गया था, जिससे उसे AI उपकरणों और चिप्स की पहुंच में बाधा उत्पन्न हो सकती थी, जबकि वह एक लोकतांत्रिक सहयोगी है।
    - इस फ्रेमवर्क का रद्द होना भारत के लिए सहयोग का बेहतर अवसर प्रदान करता है, लेकिन रणनीतिक बाधाएँ अब भी बनी हुई हैं।

रणनीतिक बदलाव, न कि नीति परिवर्तन:

- **ट्रम्प प्रशासन** ने इस फ्रेमवर्क को रद्द कर दिया, लेकिन **प्रतिबंधात्मक उपाय जारी हैं:**
    - निर्यात नियंत्रणों का विस्तार और चीनी कंपनियों की **ब्लैकलिस्टिंग**।
    - **चिप में निगरानी विशेषताओं**, स्थान ट्रैकिंग, और हार्डवेयर-आधारित उपयोग प्रतिबंधों का प्रस्ताव।
    - ये कदम व्यापार-आधारित नीतियों के बजाय **तकनीकी प्रवर्तन** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उभरती चिंताएँ:

1. **निगरानी और गोपनीयता:**
    - इन-बिल्ट ट्रैकिंग तंत्र डेटा गोपनीयता, संप्रभुता और उपयोगकर्ता स्वायत्तता पर चिंता पैदा करते हैं।
    - वैध उपयोगकर्ताओं और मित्र देशों को अमेरिका-केन्द्रित मानकों में बंधा महसूस हो सकता है, जिससे विश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती है।
2. **भू-राजनीतिक रणनीति (Geopolitical Hedging):**
    - देश अमेरिकी AI अवसंरचना पर निर्भरता कम करने के प्रयास में स्वदेशी या वैकल्पिक तंत्र (जैसे EU की AI रणनीति, भारत का BharatGPT, चीन का AI नियमन) में निवेश कर सकते हैं।

3. **वैज्ञानिक विखंडन (Scientific Fragmentation):**
    - जैसे-जैसे वैज्ञानिक खुलापन तकनीकी राष्ट्रवाद में बदलता है, AI अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है।

भारत के लिए प्रभाव:

- **अवसर:**
    - फ्रेमवर्क हटने के साथ, भारत के पास द्विपक्षीय AI साझेदारी को मजबूत करने और संतुलित वैश्विक AI शासन की वकालत करने का अवसर है।
    - भारत ऐसे फ्रेमवर्क को बढ़ावा दे सकता है जो पहुंच, नैतिकता और नवाचार को एक साथ बनाए रखे।
- **चुनौतियाँ:**
    - भारत को भविष्य में निर्भरता से बचने के लिए स्वदेशी AI हार्डवेयर और अवसंरचना में निवेश करना होगा।
    - अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए तकनीकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए रणनीतिक कूटनीति आवश्यक होगी।

निष्कर्ष:

AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क की वापसी आशाजनक प्रतीत होती है, लेकिन यह रणनीतिक सोच में बदलाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक पुनर्संरेखन है। अमेरिका संभवतः तकनीक में ही नियंत्रण तंत्र को समाहित कर AI नेतृत्व की अपनी नीति को जारी रखेगा। भारत जैसे वैश्विक खिलाड़ियों के लिए यह रणनीतिक स्वायत्तता, सक्रिय कूटनीति, और स्वदेशी AI नवाचार में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है। AI प्रसार को प्रबंधित करने के लिए एक संतुलित, सहयोगात्मक वैश्विक ढांचा चाहिए, न कि एकपक्षीय प्रतिबंधों और निगरानी आधारित दृष्टिकोण।